

भारत सरकार  
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या. 1371  
(सोमवार, 08 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

वित्तीय जागरूकता को मजबूती

1371. श्री दर्शन सिंह चौधरी:

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार ने वित्तीय जागरूकता को मजबूत करने, पहुंच बढ़ाने और इंटरैक्टिव प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू करने के लिए कौन-कौन से उपाय किये हैं;
- (ख) उक्त पहल के तहत अब तक कितने जागरूकता कार्यक्रम/शिविर आयोजित किये गए हैं तथा इसमें कौन-कौन से राज्य और संघराज्य क्षेत्र शामिल रहे हैं;
- (ग) क्या निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) ने वित्तीय शिक्षा और सेवाओं की अंतिम स्तर तक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु किसी संस्थान या जन-भागीदारी वाले संगठनों के साथ साझेदारी की है; और
- (घ) यदि हाँ, तो अब तक की उपलब्धियाँ सहित पूरे देश में "इंवेस्टर दीदी" पहल को और व्यापक बनाने के लिए भविष्य की कार्य-योजना क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): वित्तीय साक्षरता के लिए किए जा रहे उपाय इस प्रकार हैं:

- (i) वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) परियोजना भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा वित्तीय साक्षरता के लिए समुदाय के नेतृत्व वाले अभिनव और सहभागी दृष्टिकोण को अपनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। देश भर में कुल 2,421 सीएफएल स्थापित किए गए हैं, जिनमें से एक सीएफएल औसतन तीन ब्लॉकों को कवर करता है।
- (ii) बैंक अपने वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) के माध्यम से यूपीआई के माध्यम से "गोइंग डिजिटल" और आम जनता के लिए \*99# (यूएसएसडी) और विभिन्न लक्षित समूहों के लिए तैयार किए गए शिविरों का आयोजन करते हैं।
- (iii) बैंकों की ग्रामीण शाखाओं को प्रति माह एक शिविर आयोजित करना होता है जिसमें उन सभी संदेशों को शामिल किया जाता है जो वित्तीय जागरूकता संदेश (फेम) पुस्तिका का हिस्सा हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बुनियादी बैंकिंग, डिजिटल

वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण आदि सहित वित्तीय साक्षरता के विभिन्न पहलुओं पर संदेश शामिल हैं।

- (iv) देश भर में जनता के सदस्यों के बीच विभिन्न विषयों पर वित्तीय शिक्षा के संदेश का प्रचार करने के लिए 2016 से हर वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडब्ल्यू) आयोजित किया गया है।
- (v) भारतीय रिज़र्व बैंक का मल्टी-मीडिया, बहुभाषी जन जागरूकता अभियान, जिसका शीर्षक "आरबीआई कहता है" है, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने और सुरक्षित बैंकिंग कार्यप्रणालियों पर जनता को शिक्षित करने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करता है।
- (vi) निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) द्वारा देश भर में निवेशक जागरूकता कार्यक्रम (आईएपी) चलाए जा रहे हैं। इन आईएपी के अंतर्गत शिविरों का आयोजन करके वित्तीय साक्षरता और जागरूकता प्रदान की जाती है। "निवेश दीदी" एक ऐसी पहल है जिसमें एसएचजी और महिला मंडलों की मदद से आंगनवाड़ियों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), पंचायत हॉल और केवल महिलाओं की सभाओं में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। निवेशक दीदियां घरों और आस-पड़ोस का भी दौरा करती हैं, वित्तीय शिक्षा को उनके दरवाजे तक लाती हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां गतिशीलता प्रतिबंधित है।

(ख): निवेशक दीदी के अंतर्गत आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों/शिविरों की संख्या का ब्यौरा अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

(ग) और (घ): निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) ने पूरे भारत में 68738 से अधिक लाभार्थियों तक पहुंचने वाले 1110 शिविरों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए "निवेशक दीदी" कार्यक्रम के तहत इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) के साथ भागीदारी की थी। अखिल भारतीय स्तर पर इस पहल की पहुंच और परिणाम का विस्तार करने के लिए निवेशक दीदी चरण II 7 अप्रैल, 2025 को शुरू किया गया है। निवेशक दीदी चरण-II में देश भर में महिलाओं सहित ग्रामीण और अर्ध-शहरी आबादी को लक्षित करते हुए जिम्मेदार निवेश, धोखाधड़ी की रोकथाम और डिजिटल बैंकिंग पर 4000 वित्तीय साक्षरता शिविरों की परिकल्पना की गई है। लगभग 40,000 महिला डाक कर्मचारियों को सामुदायिक वित्तीय शिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। यह पहल जमीनी स्तर पर वित्तीय शिक्षा प्रदान करने के लिए डाक कर्मचारियों की व्यापक ग्रामीण उपस्थिति का लाभ उठाती है।

\*\*\*\*\*

आयोजित निवेशक दीदी जागरूकता कार्यक्रमों/शिविरों का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण  
[2022-23 से 2025-26 (सितंबर, 2025 तक)]

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-23 (चरण- I)	2023-24 (चरण- I)	2025-26 (सितंबर 2025 तक) (चरण- II)	आयोजित शिविरों की संख्या (चरण- I और II)
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	3	3
2.	आंध्र प्रदेश	-	50	113	163
3.	असम	-	7	-	7
4.	बिहार	-	19	-	19
5.	चंडीगढ़	-	1	-	1
6.	छत्तीसगढ़	-	21	32	53
7.	दिल्ली	-	11	4	15
8.	गुजरात	-	29	4	33
9.	हरियाणा	-	54	-	54
10.	हिमाचल प्रदेश	-	25	5	30
11.	जम्मू और कश्मीर	2	11	5	18
12.	झारखंड	-	8	16	24
13.	कर्नाटक	-	67	74	141
14.	केरल	-	35	13	48
15.	मध्य प्रदेश	2	88	30	120
16.	महाराष्ट्र	2	34	-	36
17.	मणिपुर	-	-	4	4
18.	मेघालय	-	6	-	6
19.	मिजोरम	8	6	-	14
20.	नागालैंड	-	10	-	10
21.	ओडिशा	-	96	65	161
22.	पुडुचेरी	-	6	2	8
23.	पंजाब	-	21	-	21
24.	राजस्थान	-	22	10	32
25.	सिक्किम	-	-	5	5
26.	तमिलनाडु	2	269	78	349
27.	तेलंगाना	-	45	92	137
28.	त्रिपुरा	-	2	4	6
29.	उत्तर प्रदेश	-	80	65	145
30.	उत्तराखंड	-	20	5	25
31.	पश्चिम बंगाल	2	49	153	204
	<b>कुल योग</b>	<b>18</b>	<b>1092</b>	<b>782</b>	<b>1892</b>